

राजधानी में टाई महीने से और बद से बदतर हो गई पार्किंग समस्या

बिना मरीन-पर्ची की पार्किंग, वाहनों को नहीं मिल रही जगह व नगर निगम को नहीं मिल रहे ठेकेदार

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

राजधानी में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को लेकर गतिरोध, विवाद और जबरिया वसूली जैसे कई दौर साथ चल रहे हैं। अपनी वाहनचालक यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी जगह वैध पार्किंग स्थल और कौन से अवैध।

आलम यह है कि बिना पर्ची की बछड़ा लगाए कछु कथित पार्किंग कर्मचारी वाहनों से रूपये वसूल रहे हैं। कृष्ण वाहन पहले सभी पार्किंग में फिरोज़ मरीन से रसीद जारी करने का निर्देश भी दिया गया, परंतु शिकायतें बनी हुई हैं कि बिना रसीद शुल्क वसूली की जा रही है। दूसरी विभिन्न क्षेत्रों में पार्किंग समस्या पर राजनीतिक दबाव भी होता है। इसके कारण स्थितियां जटिल होती जा रही हैं। हाल ही में नगर निगम द्वारा शहर की 42 पार्किंग स्थल में से सात के लिए टेंडर जारी किए गए हैं, लेकिन महज दो पार्किंग के लिए ही ठेकेदारों ने रुचि दिखाई।

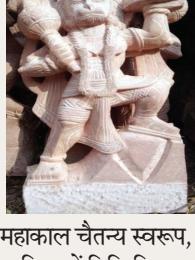


पार्किंग को ठेके पर देने के लिए हाल में टेंडर खोले, लेकिन केवल दो पार्किंग के लिए ही प्रस्ताव आए। नगर निगम के अपर आयुक्त हर्षित तिवारी ने बताया कि शेष पार्किंग के लिए फिर से टेंडर जारी किए जाएंगे। परिषद की बैठक में ममता उडने के बाद अपर आयुक्त निधि सिंहने ने अवैध पार्किंग शुल्क वसूली पर कार्रवाई करते हुए जोन 12 के जौनल अधिकारी युकेश कैमिया का हटा दिया था। इन सभी के बावजूद हकीकत यह है कि पार्किंग के मामले में

विवाद गतिरोध टाई महीने से चलने की वजह से वाहन चालकों की फज़हत ही रही है। व्यस्त क्षेत्रों में वाहन ले जाने के बाद लोगों को वाहन पाक करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बिना पर्ची के अनजान लगने वाले लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। एमपी नारा, न्यूमार्केट, हमीदिया रोड, दस नंबर इलाका जैसे क्षेत्रों में समस्या ज्यादा बढ़ी है।

जयपुर में बनी हनुमानजी की प्रतिमा स्थापित होगी

हिरदाराम नगर, दोपहर मेट्रो।



संतनगर की तुकड़ा माता मंदिर में श्रीराम भक्त हनुमानजी की मूर्ति को जयपुर के कारोगर ने आकार दिया है। मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए शीघ्र ही जयपुर से उज्जैन पहुंचेंगे। जहां शिरो के जल में संत-महात्माओं द्वारा अधिष्ठित किया जाएगा।

इसके बाद संतनगर में हनुमानजी की मूर्ति संत-

महात्माओं द्वारा शुभ मुहूर्में स्थापित की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्शा के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

आचार्य वेद पुराण प्रवक्ता अनिल रूद्र, उज्जैन

महाकाल चैतन्य स्वरूप, आचार्य लालघाटी गुफा मंदिर धाम लेखण जर्श

आईएएस अफसरों से सरकार के अनुराग का नया चित्र तैयार

भोपाल, दोपहर मेट्रो। मग्नी की यादव सरकार ने आईएएस अफसरों वाला जो बड़ा फेरबदल किया है, वह नवागत मुख्यमंत्री अनुराग जैन के नजरिए का भी पहला उदाहरण माना जा रहा है। जैन के पहले संभालों के करीब चालीस दिन बाद हुए इस फेरबदल में आने वाले प्रशासनिक समय की आहट भी है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जो प्रयोग किया गया था उसका आकार अब कम हो गया है। यहां से प्रमुख सचिव स्टर के दो अधिकारियों संजय शुक्ला व राधवेंद्र सिंह को बाहर भेजकर उन्हें स्वतंत्र लघु से विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में सीएम के अपर मुख्यसचिव राजेश राजौरा पर भी वर्कलोड बढ़ गया है। उल्लेखनीय है कि राजौरा पर लोकसेवा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है।

इस फेरबदल में कुछ और चित्र उभरे हैं, मसलन मनीष सिंह को परिवहन विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। जब यादव ने सीएम पद संभाला था, तब सिंह को काफी समय बिना विभाग रहना पड़ा था, फिर पोर्टिंग में भी काफी 'पिछड़ा' पड़ा था। बाद में वे हाउसिंग बोर्ड के जरिये कुछ मुख्यधारा में दिखे और अब



परिवहन के जिम्मे के साथ धारा में लौट आ रहे हैं। उन्हें परिवहन निगम का प्रबंध संचालक भी बनाया गया है। जात हो कि सरकार बंद हो चुके इस निगम को दोबारा जीवित

करने या ऐसा कोई नया प्रयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी तरह प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव को पशुपालन एवं डेयरी विकास की जिम्मेदारी के माध्यम से अलग हैं। दरअसल सीएम का डेयरी विकास पर खास जोर है।



बड़ा प्रशासनिक बदलाव नये संकेतों व संदेशों का जरिया बना

कई और प्रमुख तबादलों की चर्चा

- आईएएस गोतम सिंह को हटाया गया है, सिंह रिक्ल डेवलपमेंट पार्क के परियोजना संचालक थे।
- प्रमुख सचिव डॉ. ई. रमेश कुमार को हाल ही में सरकार ने एशियन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी थी जो वापस लेते हुए उन्हें अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
- प्रमुख सचिव एवं कमिशनर जनसंपर्क डॉ. सुदाम पी खाड़े के पास से माध्यम का जिम्मा वापस लेते हुए डीपीआर अंशुल गुप्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है।

दरअसल, यह बदलाव मुख्य सचिव के अब तक के

आकलन व सीएम की प्राथमिकाओं व भावी जरूरतों पर आधारित है। सुन्दरों की माने तो कुछ दिनों बाद फिर ऐसी ही एक और सूची देखने को मिल सकती है जो मंत्रालय व मुख्यमंत्री कार्यालय में फेरबदल से जुड़ी हुई होगी।

कुछ प्रभावित, कुछ बार-बार प्रभावित !

गोतरतब है कि कुछ अफसर बार बार तबादले की जद में आ रहे हैं। मसलन शहडोल सभाग के आयुक्त श्रीमन शुक्ला को दो महीने में ही वापस बुलाते हुए उनकी जगह सुरोम्बंध गुप्ता को भेजा गया है। लंबे समय से राष्ट्रीय स्तरात्मक मिशन की प्रग्नाई में एवं दिव्यांग श्रेणी (समीकरण) के शोधार्थीयों को पीएचडी शोध छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र अमर्तित किए हैं। इसके अनुसार सत्र के लिए अनुसूचित जाति जनजाति एवं दिव्यांग (दिव्यांग श्रेणी के सामाज्य-पिछड़ी वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति) के शोधार्थी, पीएचडी शोध छात्रवृत्ति के लिए 18 नवंबर 2024 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते। उक्त शोधार्थीयों को अपना आवेदन पत्र, संस्था-शोध केन्द्र से अमोजित कराकर कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, तृतीय तल सप्तपुडा भवन, भोपाल में 18 नवंबर तक जमा करना होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर नवीन निर्देश के अंतर्गत उपलब्ध है।

कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने लिया निर्णय

रिटायर्ड हो चुके 48 हजार पेंशनरों को काल्पनिक वेतनवृद्धि, पेंशन में होगा हजारों रुपए का फायदा

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

प्रदेश सरकार हर साल 30 जून व 31 दिसंबर को या उसके पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को एक अतिरिक्त काल्पनिक वेतन वृद्धि देती है। जिसकी गणना के आधार पर इन कर्मचारियों की पेंशन बनेगी और हर महीने हजारों रुपये का फायदा होगा। यह निर्णय 30 जून व 31 दिसंबर 2023 को रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों के लिए प्रभावी होगा और आने वाले सालों में उक्त तारीखों को रिटायर्ड होने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके द्वारा एवं करीब 48 हजार कर्मचारी आएंगे। इस पर सरकार को कीबी 50 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इतना फायदा इन कर्मचारियों को पेंशन में होगा। मोहन सरकार ने मामलाकारी कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया है।

एक दिन के अंतर के कारण छूट जाते थे ये कर्मचारी। रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को साल में दो बार 1 जुलाई व 1 जनवरी को वेतनवृद्धि मिलती है लेकिन 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी मध्य के एक दिन के अंतर के कारण इस दायरे से बाहर हो जाते थे। कर्मचारी मामलों के जानकारों का कहना है कि इस तरह हर 6 महीने में मिलने वाली वेतनवृद्धि में से कोई कर्मचारी आधे से अधिक अवधि तक काम करने के बाद सेवानिवृत्त होते थे तब भी उन्हें यह लाभ नहीं मिलता था, जो कि गलत था। कुछ कर्मचारी को उत्तर चले गए थे। कोटा ने उक्त मामले में वेतनवृद्धि देने के निर्देश दिए थे। जिसमें सरकार ने इस मामले में एकमुश्त निर्णय लेते हुए सभी को यह लाभ देने के प्रस्ताव को मंजुरी दी दी है।

उद्योगों के लिए अतिरिक्त जमीन देगी सरकार: नर्मदापुरम याखन नारा दिश्त मोहनसामाजिक नियमों के लिए उत्पर्करणों का नियमन करने वाली औद्योगिक इकाईयां लगानी हैं। यहां उक्त इकाईयों का एक अलग क्षेत्र विकासित होना है। इसका नियम पिछली कैबिनेट बैठक में हो चुका था। अब उक्त इकाईयों के

आसपास यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए द्वारकाधीश बड़ा मंदिर पहुंची २याम जन्मोत्सव मना, निकाली निशान यात्रा

इटारसी, दोपहर मेट्रो।

शहर में श्याम बाबा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधार से मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव के पहले चरण में श्याम प्रेमियों द्वारा भावी निशान यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए द्वारकाधीश बड़ा मंदिर पहुंची। निशान यात्रा का जगह-जगह पर धर्म प्रेमियों द्वारा स्वागत अभिनन्दन किया गया। निशान यात्रा में सांसद दर्शन सिंह चौधरी भी शामिल हुए, यात्रा के समाप्त के बाद सभी श्याम प्रेमियों को निशान भी बाटे गए। बुधवार को सूरजगंग चौक पर केक काटा जायेगा और विशाल घंडारे का आयोजन किया जायेगा।



तुलसी एवं शालिग्राम का विवाह



शुपुरी कुमारी मेघ पटेल दुल्हन बनी थी। तुलसी विवाह सुपुरी द्वारा शिक्षक एवं उनकी धर्मपत्नी किरण द्वारा आयोजित गया था। भगवान विष्णु शालिग्राम के साथ सात फेरे श्री दुर्गा पूजा का आकर्षक मंडप बनाया गया था।

बड़ा प्रशासनिक बदलाव नये संकेतों व संदेशों का जरिया बना



थियोरेटिकल ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान ज्यादा आवश्यक: डॉ. शुक्ला

16 देशों के प्रतिमार्गियों के साथ निटर भोपाल और सीपीएससी, मनीला ने शुरू किया प्रशिक्षण

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

राजधानी स्थित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर) भोपाल एवं सीपीएससी मनीला द्वारा 5 दिवसीय संयुक्त इंटर्नेशनल ड्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें 16 देशों के प्रतिमार्गियों भाग ले रहे हैं। तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को सशक्त बनानारू भविष्य के कौशल और उभरती प्रौद्योगिकीयों पर एक पहल विषय पर आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 16 देशों के प्रतिमार्गियों शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के उद्दान सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. के शुक्ला निवेशक, मैनिट, भोपाल ने कहा कि आज थियोरेटिकल ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान ज्यादा आवश्यक है। प्रैक्टिकल ज्ञान व्यक्ति को उन स्थितियों और चुनौतियों से रुक्खर करता है, जो केवल किताबों या सिद्धांतों से समझी नहीं जा सकती। आज विद्यार्थी बड़े बड़े जर्नल्स में रिसर्च पेपर्स तो पब्लिश कर रहे हैं, परन्तु कई बार छोटी-छोटी स्लिक्टल्स सीखना भूल जाते हैं। मनीला के डॉ. केशवन उलगानाथन एवं कायर्क्रम के समन्वयक डॉ. राजेश खंडवायत ने 5 दिवसीय कायर्क्रम की विस्तृत स्ल्यूरेशन प्रदान की तथा कायर्क्रम का संचालन अनीता लला ने किया। सीपीएससी, मनीला के महानिवेशक, डॉ. एस.के. धर्मेजा, ने कहा कि सीपीएससी, दुनिया भर में शिक्षा के तरीके में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहा है, शिक्षकों को भी अपने अपने को अपनी रिक्लिक्स और दक्षता बढ़ानी होगी। आज पारंपरिक शिक्षण की जगह समस्या-आधारित शिक्षण अधिक प्रासारित है।

संपादकीय

मुफ्त के वादों का आधार

ज आज ज्ञारखड में विधानसभा चुनाव के लिये बाट डाले जा रहे हैं। यह पहला चरण है, दूसरे चरण का मतदान महाराष्ट्र के साथ बीस नवंबर को होगा। दोनों राज्यों में सियासी तस्वीर बहुत उलझी हुई है। खासतौर पर महाराष्ट्र जैसे विशाल राज्य की बात करें तो यहां जिस तरह से दोनों प्रमुख गठबंधनों यानि सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने चुनावी वादों का पिटारा खोल रखा है, वह बताता है कि इन दलों ने हाल के अनुभवों और अपने नेताओं की नसीहतों से कोई सीधी नहीं ली है। यह बात बार-बार कही जाती रही है कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान वादे करने में अतिरिक्त उदारता दिखाते हैं, जिससे एक तरफ खजाने पर बोझ बढ़ता है तो दूसरी तरफ इन दलों की साख पर भी सवाल उठते हैं। उदाहरण तो कर्नाटक का भी है, जहां अव्यावहारिक वादों के बल पर चुनाव जीतने के बाद राज्य सरकार के लिए उन्हें पूरा करना मुश्किल साबित हो रहा है। सभवत-इसीलिए उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के बादे पर

**जो व्यापता अपना लक्ष्य तय
नहीं कर सकता, वह जीत भी
नहीं सकता।**

-पाण्डित

आज का इतिहास

1

नम सापता ह...



- अङ्गेय -

उदास न हो
 पर उदासी के बिना रहा
 कैसे जाए?
 शहर के दूर के तनाव-
 दबाव कोई सह भी ले,
 पर यह अपने ही रचे
 एकांत का दबाव सहा
 कैसे जाए!
 वह कहूँ भी तो सुनने के
 कोई पास न हो
 इसी पर जो जी में उठे वह
 कहा कैसे जाए!

बंगाल में बाल विवाह समस्या: राज्य अपने गौरवशाली इतिहास को चुनौती दे रहा

■ मानादापा बनजा

सु दिशा-निर्देश जारी किए हैं – परिचय बंगाल के लिए एक जटिल मुद्दा, जो अभी भी अतीत में फंसा हुआ लगता है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर जिले में एक बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किया जाए जो इस तरह के विवाहों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखे। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए पहले भी इसी तरह के नियम बनाए गए हैं, जिसे सामाजिक वैज्ञानिक गरीबी, अशिक्षा और परंपरा पर दोष देते हैं और जबकि इन प्रयासों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ा है – राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में बाल विवाह 1992-93 में 54.2 प्रतिशत से घटकर 2019-21 में 23.3 प्रतिशत हो गया है – परिचय बंगाल लगभग 41 प्रतिशत पर स्थिर रहा है, जो खुद को बिहार और त्रिपुरा के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक बनाता है। परिचय बंगाल में बाल विवाह की स्थिरता है।

यह अपने खुद के गैरवशाली इतिहास को चुनावी दे रहा है। राज्य में इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए सब कुछ है।

परंपरा से शुरुआत करें। याद रखें कि बंगाल ने लगभग 200 साल पहले सती प्रथा को समाप्त कर दिया था और 25 साल बाद विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की थी। हाल ही में, राज्य ने अपने कन्याश्री प्रकल्प कार्यक्रम के लिए यूनिसेफ से प्रशंसा पाई – लड़कियों को स्कूल भेजने और बाल विवाह को रोकने के लिए नकद हस्तांतरण



अभी भी कम उम्र में शादी कर रही हैं।
हालांकि, हैरान नौकरशाह, समाज वैज्ञानिक

ओर अथशास्त्रों एक ऐसा घटना में आशा का किरण देख रहे हैं, जिसे अधिकारिक तौर पर सारणीबद्ध नहीं किया गया है, लेकिन यह अधिक साफ होती जा रही है: स्व-प्रेरित शादी. ज्यादातर लड़कियां 18 साल की होने से ठीक पहले शादी कर रही हैं, एक तरह से, अपने साथी को चुनने वे अपने अधिकार का दावा कर रही हैं, भले ही इसका मतलब राज्य से मिलने वाले वित्तीय लाभ को खोना हो. लड़कियां 18 वर्ष की आयु तक इंतजार के लिए तैयार नहीं हैं और अपने माता-पि द्वारा उन्हें अपनी पसंद की शादी के लिए मजबूर

उनकी पसंद की। लड़कियां विद्रोह कर रही हैं,
मुखर हो रही हैं – और यह जश्न मनाने की बात है,
भले ही इससे पश्चिम बंगाल के बाल विवाह के
आंकड़े नष्ट हो जाएं। लेकिन शिक्षा के बारे में क्या?
18 वर्ष की आय से कछक्कम आय में स्व-परिव

18 वर्ष का जानु से लूँछ बन जानु है स्वत्रारा
 शादी के टेंड ने कुछ समाज वैज्ञानिकों को यह
 पहचानने पर मजबूर कर दिया है कि पढ़ने के लिए
 शिक्षा पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं है।

लड़कियां और लड़के – जो अपनी जिंदगी के
 लगभग 18 साल स्कूल में बिताते हैं, वह उस
 निवेश पर सार्थक रिटर्न चाहते हैं, लेकिन नौकरियों
 की कमी को देखते हुए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए
 कुछ खास नहीं मिलता। इसलिए, लड़कियों के

हाथपाल पर्णिमा बंगाल के दीन चिल्हों को

दरअसल, पाश्चम बंगाल के तानाजिला की बाल विवाह के मामले में सबसे खराक प्रदर्शन करने वाले जिलों के रूप में फहचाना जाता है – मुर्शिदाबाद, पश्चिम मिदनापुर और पूर्वी मिदना-विडंबना यह है कि पूर्वी मिदनापुर में राज्य में सभी अधिक साक्षरता दर भी है। साक्षरता लड़कियों के लिए कम उम्र में शादी न करने का कोई कारण नहीं है। असल में, साक्षरता संभवतः उनके दृढ़ संकल्प और अपने साथी को खुद चुनने के दृढ़ संकल्प बढ़ावा दे सकती है, भले ही वे कम उम्र के हों। न सामने जो समस्या है वह यह है कि शादी किससे करें? पश्चिम बंगाल में लड़के खतरनाक दर से स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि लगभग सभी प्रोत्साहन-लड़कियों पर केंद्रित हैं, जिससे लड़के यूं ही रहते हैं – जिससे लड़के यूं ही रहते हैं –

जात है। इसलिए, सकंट का प्रश्नात में, अगर उके परिवार को पैसे कमाने के लिए अतिरिक्त हाथों जरूरत होती है, तो चलन यह है—चलो लड़के के स्कूल से निकाल दें—लड़की को नहीं। वह कम कम सरकारी अनुदान प्राप्त करके परिवार के खाली में योगदान दे रही है, लड़का नहीं, इसलिए चलो उसे काम पर लगा दें।

इसका नतीजा यह है कि पश्चिम बंगाल में लड़कों से ज्यादा लड़कियां माध्यमिक परिक्षा दे रही हैं, लड़कियों के स्कूलों में कक्षाएं भरी हुई हैं, जबकि लड़कों के स्कूल खाली हो रहे हैं। नतीजे युवा पुरुषों की एक नस्ल बन रही है जिनकी शिक्षा अधूरी है, जिन्हें कम उम्र से ही व्यावसायिक कौशल के जरिए परिवार के लिए पैसे कमाने के

लिए तैनात किया जाता है, जो कि बहुत उच्चल संभावनाओं वाले नहीं होते।

कह लड़क काम का तलाश मधर छाड़न क
लिए मजबूर होते हैं, अक्सर राज्य के बाहर और
जब माता-पिता उन्हें परिवार और घर से बांधना
चाहते हैं, तो उनका समाधान होता है-उसकी शात
कर देना। कोई भी माता-पिता नहीं चाहते कि
उनकी बहु बेटे से ज्यादा पढ़ी-लिखी हो या बड़ी
हो। इसलिए, अपने 18-वर्षीय स्कूल छोड़ने वाले
बेटे के लिए, जो प्रवासी मजदूर बनने की कगार
पर है, वह ऐसी दुल्हन की तलाश करते हैं जो कम
उम्र की हो, कम पढ़ी-लिखी हो। अंतिम परिणाम?
पश्चिम बंगाल के बाल विवाह के आंकड़ों के
ताबूत में एक और कील।

निर्देश स्वागत योग्य है, लेकिन वह भारत को बनाने वाली अनंत सामाजिक-आर्थिक जटिलताओं से नहीं निपटते। आइए इस बात पर ध्यान न दें कि ये नियम विभिन्न धार्मिक आदेशों के व्यक्तिगत कानूनों को पीछे छोड़ते हैं या नहीं।

अच्छी खबर यह है कि बाधाओं के बावजूद, भारत में बाल विवाह की दर में कुल मिलाकर गिरावट आई है। सूची में सबसे नीचे रहने वाले राज्यों ने बड़ी छलांग लगाई है। पश्चिम बंगाल के लिए आगे का रास्ता सहयोग करना और अन्य राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना होना चाहिए। बाल विवाह की बुराई को खत्म करना होगा। पश्चिम बंगाल पीछे नहीं रह सकता — इसके लोग इससे बेहतर के हकदार हैं।

(साभार : लेखक वरिष्ठ पत्रकार है)

विद्यार्थियों ने मारी बाजी, महाविद्यालय का नाम किया रोशन

इटारसी, दोपहर मेट्रो

शासकीय महाता गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय इटारसी के प्रतिभागियों ने सोमवार को जिला स्तर प्रायोजित विभिन्न महाविद्यालय में युवा उत्सव की एकांकी, बाद विवाद, भाषण, कार्योंगत, प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें सभी पांचों विधाओं में शासकीय एमजीएम महाविद्यालय इटारसी के प्रतिभागियों ने पांचों विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय

में कीर्तिमान स्थापित कर महाविद्यालय को गौर्बान्वित किया। कार्योंगत विद्या में मश्रूम चौधरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया यह प्रतियोगिता शासकीय माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय माखन नार में संपन्न हुई।

वाद

प्रतियोगिता के पक्ष में तृष्णी औमकार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया बाद विवाद प्रतियोगिता के विषय में महाविद्यालय की छात्रा को मपल मनवारे ने विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भाषण



प्रतियोगिता में महाविद्यालय की

छात्रा को मपल मनवारे प्रथम स्थान

प्राप्त किया। एकांकी विधा में ओम

सिंह, गोता चौहान, सुष्ठि सिंह, मंयक कर्मांजीय, अमित पुरी गोस्वामी, अभिषेक सोनी, शशिका पांडे, हिरेश मेहरा ने 'अब क्या' विषय पर प्रथम स्थान प्राप्त किया यह एकांकी महाविद्यालय के डॉ. दिनेश कुमार द्वारा निर्वाचित था।

महाविद्यालय की प्राचीर्य डॉ. राकेश मेहता ने सभी प्रतिभागियों को महाविद्यालय परिवार की ओर से बधाई प्रेषित करते हुए कहा कि ऐसे विद्यार्थी महाविद्यालय के गौरव है, जिसी महाविद्यालय की प्रतिष्ठा है,

आले स्तर पर पहुंचकर महाविद्यालय का नाम गोर्बान्वित करेंगे ऐसी शुभकामनाएं में प्रेषित करती हैं।

युवा उत्सव प्रभारी डॉ. संतोष कुमार अहिवार युवा उत्सव प्रभारी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। 12 नवंबर 2024 को महाविद्यालय में यायन की पांच विधाएं संपन्न होंगी। इन विधाओं में प्रतिभागिता करने वाले सभी विद्यार्थीयों को भी अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की।

विधिवत परीक्षण करने के लिए सीएमओ को निर्देश

तूल पकड़ रही है नपा में बरसों पूर्व हुई अनुकंपा नियुक्ति

■ मजदूर संघ ने कहा-हम इस निर्देश को लेकर उत्साहित नहीं है क्योंकि संयुक्त संचालक के निर्देश पर कार्यवाही नहीं करेंगे बल्कि उसे ढंगे बरसे में डाल दी जाएगी।

■ सीएमओ अपने घरें को रिकायत होने वाले जूट स्थापना, लेखा शाखा से न हटाकर शासन के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं।

नर्मदापुरम, दोपहर मेट्रो

नगर पालिका कर्मचारी मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार वर्मा ने बताया है कि कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक नारीय प्रशासन एवं विकास नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम कार्यालय से पर क्रमांक - संस/अनु.नि./नर्मदापुरम/482 नर्मदापुरम दिनांक - 21/10/2024 संयुक्त संचालक से प्राप्त उत्तर दोपहर संधे के द्वारा 07/10/2024 को मजदूर संघ के द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र में कहा गया था कि शासन स्तर पर दी गई अनुकंपा नियुक्तियों को क्रमांकित किया जाएगा। इसको लेकर कर्मचारी अधिकारी अवमानना कर रहे हैं। ऐसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी से क्या उमंदी को जा सकती है।

क्या है मालाला..?

महेश कुमार वर्मा ने बताया कि नर्मदापुरम, दोपहर मेट्रो

नगर पालिका कर्मचारी मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार वर्मा ने बताया है कि कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक नारीय प्रशासन एवं विकास नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम कार्यालय से पर क्रमांक - संस/अनु.नि./नर्मदापुरम/482 नर्मदापुरम दिनांक - 21/10/2024 संयुक्त संचालक से प्राप्त उत्तर दोपहर संधे के द्वारा 07/10/2024 को मजदूर संघ के द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र में कहा गया था कि शासन स्तर पर दी गई अनुकंपा नियुक्तियों को क्रमांकित किया जाएगा। इसको लेकर कर्मचारी अधिकारी अवमानना कर रहे हैं। ऐसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी से क्या उमंदी को जा सकती है।



कर्मचारी जो कि पिता के शासकीय सेवा काल में रहे होने के पश्चात जाची यानि मृतक कर्मचारी जो नगरपालिका में चपरासी के पद पर पदस्थ था दिये गये शपथकर के अनुसार जाचा ने जिस भर्तीजे को पहला नामिनी बनाया था उस के स्थान पर पहले नामिनी की स्वीकृति पर दूसरे भर्तीजे को नामिनी तैयार करके मूर्छित अवस्था में शपथपत्र बनवाया गया। नामिनी फार्म पर जाचा के अस्पष्ट हस्ताक्षर करवाकर चपरासी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की गई। मूर्छित कर्मचारी हस्ताक्षर करने के लिए गया। कर्मचारी अध्यक्ष वर्मा ने बताया नगरपालिका में पदस्थ चार कर्मचारीयों के द्वारा आमतौर पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रदान किया जाएगा।

अधिकारी जो कि पिता के शासकीय सेवा काल में रहे होने के पश्चात जाची यानि मृतक कर्मचारी जो नगरपालिका में चपरासी के पद पर पदस्थ था दिये गये शपथकर के अनुसार जाचा ने जिस भर्तीजे को पहला नामिनी बनाया था उस के स्थान पर पहले नामिनी की स्वीकृति पर दूसरे भर्तीजे को नामिनी तैयार करके मूर्छित अवस्था में शपथपत्र बनवाया गया। नामिनी फार्म पर जाचा के अस्पष्ट हस्ताक्षर करवाकर चपरासी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की गई। मूर्छित कर्मचारी हस्ताक्षर करने के लिए गया। कर्मचारी अध्यक्ष वर्मा ने बताया नगरपालिका में पदस्थ चार कर्मचारीयों के द्वारा आमतौर पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रदान किया जाएगा।

नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं होने के बाबजूद विभागीय वरिष्ठ कार्यालय की अनुशंसा पर तीन अश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई हैं। चौथा अश्रित अनुकंपा के लिए आज तक वर्चित है। आम्हत्या के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देकर नगरपालिका ने अप्रत्यक्ष रूप से समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं यह समझ से परे है।

मजदूर संघ मध्यप्रदेश शासन व नगरपालिका से अपेक्षा करता है कि अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित शिकायतों की विषयकता से जाच कार्यवाही करते हुए उत्तर प्रणाम दिये जाएं। वैसे उक्त संबंधित अनुकंपा नियुक्तियों पर कार्यवाही को लेकर मजदूर संघ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश के अधिकारी अवस्था में चला गया है क्योंकि उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान, उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश से पारित आदेश व शासन आदेश के तहत दत्तक पुरुष/महिला को और आम्हत्या पर अश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के प्रावधान नहीं हैं के बावजूद अश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का पारिवर्तिक दिया गया है।

कर्मचारी अवस्था में चला गया है क्योंकि उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान, उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश से पारित आदेश व शासन आदेश के तहत दत्तक पुरुष/महिला को और आम्हत्या पर अश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के प्रावधान नहीं हैं के बावजूद अश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का पारिवर्तिक दिया गया है।



10 दिवसीय एनसीसी प्रशिक्षण शिविर शुरू

नर्मदापुरम, दोपहर मेट्रो

एनसीसी महानिवेशक एवं ग्रुप हैडकारर भोपाल के तत्वावादी में 13 एम.पी. बटालियन एनसीसी के द्वारा 10 दिवसीय एनसीसी प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। यह शिविर 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक संचालित होगा। इस शिविर में 359 कैटड भारीदारी कर रहे हैं। इस शिविर में 13 एम.पी. बटालियन एनसीसी नर्मदापुरम के 285 एवं 4 एम.पी. एनसीसी गर्ल्स बटालियन के 74 सीनियर और जूनियर डिवीजन के कैटड भारीदारी कर रहे हैं। कर्मचारी अवस्था में शपथपत्र बनवाया गया। नामिनी फार्म पर जाचा के अस्पष्ट हस्ताक्षर करवाकर चपरासी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की गई। मूर्छित कर्मचारी हस्ताक्षर करने के लिए गया। कर्मचारी अधिकारी अवस्था में शपथपत्र बनवाया गया। नामिनी फार्म पर जाचा के अस्पष्ट हस्ताक्षर करवाकर चपरासी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रदान किया जाएगा।

प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिसमें मैप रिडिंग, फोलेड

क्रापट, बैटल क्रापट, एवं अन्य सैन्य विधयों की जानकारी दी जाएगी।

जाएगी। इसके अतिरिक्त इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जिसमें निवांधि, लेखन, चित्रकारी, ताल्कालिक भाषण, खेल एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जाएंगे। कैपें के शुभारंभ करते हुए अपने ओपनिंग एड्रेस में कर्नल हरप्रीत सिंह की शिविर का उद्घास्य कैटड को उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना और कैटड के व्यक्तित्वात्मक अवस्था को नियन्त्रित करने के लिए गया। साथ ही इसके बावजूद एकांकी के शिविर का उद्घास्य करना और अनुकंपा नियुक्ति का प्रदान किया जाएगा।

इसी अवसर पर यूनियन बैंक के 106 वर्ष पूर्ण होने पर

किसानों को परेशान करने वाले नर्मदा वेयरहाउस में अब नहीं होगी तौल

सिरोंज, दोपहर मेट्रो

किसानों की फसल को अमानत बढ़कर भंडारण करने में आना-कानी करने वाले नर्मदा बड़ा उसको पड़ा महांगा लेकर ने यहां पर तुलाई और भंडारण करता दिया। सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर समितियों के माध्यम से सोयाबीन की खरीदारी कराकर पास के वेयरहाउसों पर तोल करवा कर भंडारण करता जा रहा है। पिछले कई दिनों से भंडारण के दौरान नर्मदा वेयरहाउस पर किसानों की उपज

सियलपुर समिति से हो रही थी खरीदारी सर्वेयर को भी किया निलंबित

तुलाई करने के बाद खरें में उन्हें परेशान किया जा रहा था किसानों को परेशान करना नर्मदा वेयरहाउस संचालक को महांगा पड़गया कलेक्टर ने एसडीएम की रिपोर्ट पर उसको हटा दिया है। सियलपुर



समिति के नर्मदा वेयरहाउस के संचालक द्वारा समिति द्वारा उपार्जन किए गए सोयाबीन को अमानक बताकर वेयरहाउस में प्राप्त करने में असहमति व्यक्त के जा रही थी। जिसमें दिनांक 11.11.2024

किसान भी परेशान हो रहे थे कई दिनों तक उनकी ट्रैक्टर द्वारा यहां पर खड़ी रही थी। एसडीएम ने जांच के बाद वेयरहाउस में तोल रोकने लिए कलेक्टर को जांच प्रतिवेदन भेजा था। कलेक्टर ने किसानों के द्वितीय में निर्णय लेते हुए नर्मदा वेयरहाउस पर तोलकाल तुलाई बंद करवा दी है। सोमवार को एसडीएम हर्षल चौधरी धरी ने मैके पर पहुंचकर, समिति प्रबंधक, वेयरहाउसिंग के अधिकारी द्वारा कृषकों से चर्चा कर शीघ्र उनकी

समस्या के नियरकरण हेतु समझाइए दी गई। कलेक्टर से चर्चा उपरांत संबंधित वेयरहाउस के विस्तर पंचानाम बनाया गया एवं उसकी मैटिंग को दिया गया। समीप में स्थित स्वास्थित वेयरहाउस के मैटिंग करवाई गई एवं उसमें सभी कृषकों की तुलाई का कार्य प्रारंभ करवाया गया। कृषकों से चर्चा उपरांत सर्वेयर की शिकायत प्राप्त हुई जिसपर तोलकाल कार्यवाही करते हुए संबंधित सर्वेयर को निलंबित करवाया गया है एवं नवीन सर्वेयर

की नियुक्ति करवायी गई है। क्योंकि यहां काम करने वाले सर्वेयर के द्वारा भी फसल पास करने का नाम पर किसानों से अवैध वसूली की जा रही थी। जिसकी शिकायत भी जांच के दौरान किसानों ने थी।

इनका कहाना है

किसानों को परेशान करने वाले नर्मदा वेयरहाउस का बदल दिया है। सर्वेयर का बदल दिया है। एसडीएम को बाद सर्वेयर को भी हटाया है।

- हर्षल चौधरी एसडीएम

भोपाल रोड पर पट्टे की जमीनों को हड्पकर काटी जा रही है अवैध कॉलोनियां

भू-माफियाओं का सरकारी जमीनों पर कट्जा, प्रशासन मौन, बढ़ रहा संकट

सिरोंज, दोपहर मेट्रो



सरकारी जमीनों पर कट्जा

भू-माफियाओं ने सरकारी जमीनों पर कट्जा करके अवैध कॉलोनियां बना डाली हैं। इन कॉलोनियों में गली-सड़कें खड़ी की गई, लेकिन न सीधेज सिर्टम है, न बिजली और न ही पानी की व्यवस्था। फिर भी, ये कॉलोनियों बेहतर सुविधा के नाम पर बेच दी जाती है।

में बेचकर, माफिया लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं। सिरोंज में मुख्य रूप से भोपाल रोड पर गरीबों को सरकार करने खेती के लिये पट्टे दिये थे और अब इन लोगों ने सरकारी जमीनों को बेचना शुरू कर दिया है इन जमीनों को भू-माफियाओं द्वारा किसानों से सर्वतो दामों पर खरीदा जा रहा है इसके साथ ही पट्टा धारक भी सरकार द्वारा दी गई कृषि भूमि को जब अवैध तरीके से कॉलोनियों में बदला जाता है, तो न केवल कृषि भूमि की उत्पादकता व्यापकिता होती है, बल्कि यह पर्यावारीण संकट भी उत्पन्न करता है। इन अवैध कॉलोनियों के निर्माण के बाद इन क्षेत्रों में जल स्तर घटता है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, और जैव विविधता भी समाप्त होती जा रही है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कृषि भूमि पर अवैध निर्माण से किसानों की आजीविका खतरे में है। इन किसानों की जमीनें नाजायज तरीके से कटाई जा रही हैं और उन्हें उचित मुआवजा या पुनर्वास कर अपने कब्जे में लेना चाहिये।

कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण

कृषि भूमि (एपीकल्चर लैंड) पर कट्जा कर के भू-माफिया ने अवैध कॉलोनियों का निर्माण शुरू कर दिया है। यह कृषि भूमि, जो पहले किसानों की आजीविका का

प्रमुख साधन थी, अब भू-माफिया के हाथों अवैध कॉलोनियों में बदल रही है। कृषि भूमि का कानूनी तरीके से इस्तेमाल न करने और उसे मूल उद्देश्य से भटकाने की प्रक्रिया अब एक बड़े संकट का रूप ले चुकी है। सरकारी योजना के तहत दी गई कृषि भूमि को जब अवैध तरीके से कॉलोनियों में बदला जाता है, तो न केवल कृषि भूमि की उत्पादकता व्यापकिता होती है, बल्कि यह पर्यावारीण संकट भी उत्पन्न करता है। इन अवैध कॉलोनियों के निर्माण के बाद इन क्षेत्रों में जल स्तर घटता है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, और जैव विविधता भी समाप्त होती जा रही है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कृषि भूमि पर अवैध तरीके से कटाई जा रही है और उन्हें उचित मुआवजा या पुनर्वास कर दिया जाए। यही नहीं, यह स्थिति उस कृषि क्षेत्र के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है, और भी सीमित होती जा रही है।

भ्रष्टाचार और प्रशासन की नाकामी

यह सारा खेल बिना स्थानीय अधिकारियों के सहयोग के सम्बन्ध नहीं हो सकता था। अरोप है कि अवैध अधिकारियों ने नर्मदा वेयरहाउस को कानूनी मंजूरी दी है, और इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। कई स्थानीय नेताओं को भी मौजूदा बदलाई जा रही है, जो इन कॉलोनियों को मंजूरी दिलाने में सहायक रहे हैं।

स्थानीय नगरियों की बिंदी हालत

इन अवैध कॉलोनियों में रहे रहे लोग अब भ्रष्टाचार के शिकाह हो चुके हैं। लोग जल संकट और बिजली की कठोरी से जुड़ा रहे हैं, और कहीं-कहीं तो स्वच्छता की गंभीर समस्या ने स्वास्थ्य संकट उत्पन्न कर दिया है। लेकिन प्रशासन मूल दर्शक बना हुआ है। इन कॉलोनियों में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता भी बेहद खराब है। ये कॉलोनियां आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए बिल्कुल असुरक्षित हैं, और भूकंप या बड़ी बारिश जैसी व्याप्ति में ये सारी कॉलोनियों ढह सकती हैं।

प्रशासन का दुरुपयोग

इन सब के बीच, स्थानीय प्रशासन का रवैया बिल्कुल लापरवाह है। इन अवैध कॉलोनियों में रहे रहे लोग अब भ्रष्टाचार के शिकाह हो चुके हैं। लोग जल संकट और बिजली की कठोरी से जुड़ा रहे हैं, और कहीं-कहीं तो स्वच्छता की गंभीर समस्या ने स्वास्थ्य संकट उत्पन्न कर दिया है। लेकिन प्रशासन मूल दर्शक बना हुआ है। ये कॉलोनियों में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता भी बेहद खराब है। ये कॉलोनियां आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए बिल्कुल असुरक्षित हैं, और भूकंप या बड़ी बारिश जैसी व्याप्ति में ये सारी कॉलोनियों ढह सकती हैं।

अवैध कॉलोनियों के लिए मंजूरी की प्रक्रिया

कई अवैध कॉलोनियों के निर्माण के लिए प्रशासन की ओर से जरूरी मंजूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जब भी कोई नई कॉलोनी विकसित की जाती है, तो उस नगर निगम, टाउन प्लानिंग, और राज्य सरकार से मंजूरी मिलनी चाही ए। यह प्रक्रिया जल आपूर्ति, सीधेज सिर्टम, सड़क, और बिजली की व्यवस्था के द्वारा होती है। लेकिन इन अवैध कॉलोनियों में से अधिकांश ने न तो जमीन का समिति सत्रानन किया और न ही आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की। इन कॉलोनियों की निर्माण सिर्प अवैध तरीके से हुआ है, जिससे लाखों लोगों को सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की भाँती कमी हो रही है।

जनता की जागरूकता और सवाल

अब शरह की जनता खुलकर सवाल उठाने लगी है कि प्रशासन क्यों इन अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। क्या लोकवान में जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? क्या भ्रष्ट अधिकारियों और भू-माफियाओं का कितना बड़ा गिरावंश तरीके से कटाया जा रहा है?

भी नहीं दिया जा रहा। यही नहीं, यह स्थिति उस कृषि क्षेत्र के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है, और अब यह और भी सीमित होती जा रही है।

जहां पहले से ही उपजाऊ जमीनों की कमी हो रही है और अब अब यह और भी सीमित होती जा रही है।

नायब तहसीलदार ने, अवैध रूप से उत्थन करने वालों की पकड़ी दी

सिरोंज। ग्राम समाप्तर ने कई दिनों से अवैध रूप से उत्थन करने वालों की पकड़ी दी।

विदिशा जन चेतना शिवालिङ्ग परिसर में सप्तप्त हुआ। प्रतियोगिता के समाप्त अवधार के लिए एसपीटीएस पूरे ट्रॉफीमें में मह

